

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 35/20

GCMS NO 2020/00089



लक्ष्मण पुत्र प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासी थडी तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

अपीलांत

बनाम

1. किशनलाल पुत्र लक्ष्मण
2. बीरवल पुत्र लक्ष्मण
3. कमल प्रसाद पुत्र प्रभूलाल
4. मु0जसोदा पत्नि स्व0प्रभूलाल
5. रामविलास पुत्र रामधन
6. जयसिंह पुत्र रामधन
7. लालाराम पुत्र रामधन
8. गुडडी पुत्री रामधन
9. मु0गुलाब देवी पत्नि स्व0रामधन जाति गुर्जर निवासीयान थडी तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
10. राजस्थान सरकार जरिये भू अवाप्ति अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर
11. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा बौली जिला सवाई माधोपुर

(अपील विरुद्ध मु0नं0 1028/18 निर्णय दिनांक 26.11.18 न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री गिर्राज सिंह गुर्जर


अभिभाषक रैस्पो0 श्री हिम्मत सिंह राजावत

दिनांक 29.9.2025


निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 26.11.18 न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौली पेश की है ।

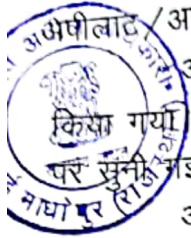
अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रैस्पो0 संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 व प्रति0संख्या 5 लगायत 9 ग्राम थडी तहसील बौली के निवासी है तथा प्रार्थीगण व प्रति0संख्या 5 ता 9 एक ही पूर्वज स्व0लक्ष्मण की संतान है। वादग्रस्त आराजीयात ग्राम थडी मे स्थित है। जिसका खाता संख्या नया 41 पुराना 63 रहा है जिसके खसरा न0 839/0.01, 840/1.37, 841/0.01,842/0.10,843/0.08,892/0.41, 892/3373/0.05 है0 रहे है इसी प्रकार खाता संख्या नया 495 पुराना 128 के खसरा न0 883/0.80, 884/0.46 रहे है। उक्त मुद्दों की


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

खातेदारी भी कालान्तर मे प्रार्थीगण के साथ 1/2 हिस्से मे मौजीराम पुत्र सीताराम के नाम नामांकन कर दिया गया जो मुकदमा संख्या 337/2000 मे पारित निर्णय दिनांक 24.4.01 व डिक्री दिनांक 27.4.01 के द्वारा प्रार्थीगण के नाम खातेदारी संपूर्ण दर्ज करने के आदेश जारी किये गये जिसकी गलती गलतना मे जमाबंदी सम्वत 2052 मे विषयक नामा0 संख्या 950 का अमल भी किया गया जिसमे राजस्व कर्मियों की गलती से उक्त नामा0 की पुनरावृति संवत 2063 की जमाबंदी मे नही उक्त आदेश एवं निर्णय व डिक्री के बावजूद आज भी जमाबंदी मे पूर्ववत इन्द्राज चला आ रहा है जो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से दुरुस्ती किया जाकर खाता संख्या 41 की सम्पूर्ण खातेदारी प्रार्थीगण व प्रति0संख्या 5 ता 9 के नाम अंकित किये जाने योग्य है। उक्त आराजीयात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 5 ता 9 के पूर्वज स्व0लक्ष्मण का कब्जा काश्त एवं खातेदारी चली आ रही थी जिसमे कभी भी किसी अन्य व्यक्ति का कोई लेना देना नही था। जो संवत 2019 से 2022 की खतौनी से स्पष्ट है। जिसका कुल रकबा 14 बीघा 13 विस्वा होता है। जिसमे से 155 का रकबा अन्य स्थान पर स्थित है जो विवादित नक्शा ट्रेस वाले स्थान पर मौजूद है वह 11 बीघा 11 विस्वा शेष रहती है। कालान्तर मे उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 के पूर्वज के नाम चली आ रही भूमि मे से रकबा 3 बीघा 11 विस्वा राजस्व कार्मिको की गलती से स्व0लक्ष्मण की खातेदारी कम हो गई एवं 11 बीघा 11 विस्वा मे से 8 बीघा अर्थात 2.03 है0 रह गई जबकि उक्त समस्त भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वज लक्ष्मण का अबाध कब्जा काश्त एवं खातेदारी रही है जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण के पुख्ता मकानाम आदि भी अपनी उक्त भूमि मे स्थित है एवं कुआ भी मौजूद है। चूकि प्रार्थीगण के पूर्वज लक्ष्मण अनपढ व्यक्ति थे जिन्होने कब्जे को ही सर्वोपरी मानकर कभी खातेदारी रिकार्ड मे गलती की ओर कोई ध्यान नही दिया जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 5 ता 9 की खातेदारी मे स्व0लक्ष्मण की खातेदारी रकबा 11 बीघा 11 विस्वा के स्थान पर 8 बीघा ही रह गई जबकि कब्जा आज भी हम वारिसान का संपूर्ण भूमि पर है। जिसमे खाता संख्या 41 की संपूर्ण भूमि के साथ साथ खाता संख्या 495 का खसरा न0 883 संपूर्ण एवं ख0न0 884 मे 0.83 है0 भूमि प्रार्थीगण एवं प्रति0संख्या 5 ता 9 की बनती है। उक्त समस्त भूमि मे अप्रार्थी संख्या 2 का कोई लेना देना नही है। यहाँ तक की अप्रार्थी संख्या 2 की कोई भूमि कब्जाशुदा,खातेदारी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 ता 9 के कुए खसरा न0 839 मे चौतरफ मौजूद नही है परन्तु सेटलमेंट कर्मियों की त्रुटि से खसरा न0 883 व 884 की खातेदारी मे अप्रार्थी संख्या 2 के नाम का अंकन कर दिया जिसे दुरुस्त कराना आवश्यक है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 का नाम हजफ करते हुए प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 ता 9 के नाम खातेदारी घोषणा किये जाने योग्य है। उक्त विवादित भूमि से एक्सप्रेस वे स्कीम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग निकलने की संभावना से उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण के साथ साथ उक्त गलत अंकन के कारण अप्रार्थी संख्या 2 उठाना चाहता है जिसे रोका जाना आवश्यक है एवं प्रार्थीगण को यह अधिकार हासिल है कि अप्रार्थी संख्या 2 को रथाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे। यदि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मुआवजा प्राप्त कर लिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 को पाबंद फरमाया जावे कि राजस्व रिकार्ड के खाता संख्या 495 मे अपने नाम का अंकन होने एवं खसरा न0 883 व 884 की जिनकी पूर्व मे प्रार्थीगण के


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पूर्वज स्व०लक्ष्मण की खातेदारी भूमि थी जिसके गलत इन्द्राज के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त भूमि में मिलने वाले मुआवजा राशि अप्रार्थी संख्या 1 व 3 अप्रार्थी संख्या 2 को प्रदान नहीं करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/रेस्पोंड संख्या 1 ता 4 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर



अपीलांत/अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब रेस्पोंड को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांत के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व कानूनी प्रावधानों का सही प्रकार से अवलोकन नहीं किया है तथा इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन की कोई तामिल नहीं हो पाई एवं एक तरफा में एक पक्षीय बहस सुनी जाकर आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि आराजी खसरा न० 883 रकबा 0.8000 एवं खसरा न० 884 रकबा 0.4600 है वाके ग्राम थडी तहसील बौली में स्थित है जो अपीलांत हरिराम ने आज से करीब 30 साल पूर्व छीतर साई पुत्र माधो साई निवासी थडी तहसील बौली से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीदी थी जब से ही मौके पर अपीलांत कब्जा काश्त करता चला आ रहा है आज भी अपीलांत का ही कब्जा काश्त है। रेस्पोंड का कोई संबंध वास्ता नहीं है एवं अपीलांत ने बीआरजीवी शाखा बौली से ऋण लेकर रहन रख रखी है जिसको अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया है। निर्णय दिनांक 24.4.01 डिक्री दिनांक 27.4.01 मु०न० 337/2000 न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाईमाधोपुर के वाद पत्र में हरिराम अपीलांत का कोई संबंध वास्ता नहीं था क्योंकि सीताराम एवं लक्ष्मण दोनों भाई थे जिनकी संतानों ने वाद पत्र पेश किया था जिससे अपीलांत हरिराम का कोई संबंध वास्ता नहीं था। रेस्पोंड 1 ता 9 का गौत्र डागुर है जबकि अपीलांत हरिराम का गौत्र बोरवाल है इसलिए अपीलांत व रेस्पोंड का कोई वास्ता नहीं है। रेस्पोंड ने अधिनस्थ न्यायालय में झूठा वाद पत्र पेश किया है एवं कोई सजरा खानदान पेश नहीं किया तथा न्यायालय को गुमराह किया है। अपीलांत की आराजी से रेस्पोंड का कोई संबंध वास्ता नहीं है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली के प्रकरण संख्या 1028/2018 में पारित आदेश दिनांक 26.11.18 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोंड के अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा न० 839,840,841,842,843,892,892/3373 कुल किता 7 कुल रकबा 2.03 है वाके ग्राम थडी तहसील बौली प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजी है जो पूर्व में 1/2 हिस्सा गंगजी, कालू, नरसी पिसरान मौजीराम व रामसुखी पत्नि मौजीराम के नाम दर्ज थी। जिसके बाबत वाद पत्र मु०न० 337/2000 न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहाँ प्रस्तुत किये जाने पर माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपने निर्णय व डिक्री 24.4.01 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

द्वारा सम्पूर्ण भूमि रेस्पो0 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। जिसकी पालना मे नामा0 संख्या 950 दिनांक 17.5.02 को खोला जाकर सम्पूर्ण रकबा प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया गया। परन्तु जमाबंदी मे उक्त नामा0 का नोट अंकित नही दोहराये जाने के कारण पूर्ववत 1/2, 1/2 हो गया। इसके आधार पर प्रार्थीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमे सिर्फ प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं क्षति को देखा जाना है। अपीलांट का कथन रहा कि अपीलांट की बिना तामिल के ही न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांट की तामिली प्रोपर उनके पिता प्रभू द्वारा प्राप्त की गई है। विवादित आराजीयात खाता संख्या 495 के ख0न0 883 व 884 की खातेदारी के विषय मे वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है जिसमे खातेदारी अधिकारो का निर्धारण साक्ष्य के उपरान्त तय होंगे। विवादित आराजीयात से अपीलांट का किसी प्रकार का कोई संबंध वास्तव में नहीं है। राजस्व कर्मियों की गलती से विवादित आराजीयात का इन्द्राज अपीलांट के नाम दर्ज होने के कारण उक्त भूमि मे से राष्ट्रीय राजमार्ग निकलाने के कारण उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर अवाप्त भूमि का मुआवजा अपीलांट लेना चाहता था जबकि अपीलांट का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध वास्तव में नहीं है। गलत इन्द्राज के आधार पर यदि अपीलांट को मुआवजा राशि प्रदान की जाती है तो प्रार्थी/रेस्पो0 को अपूर्णनीय क्षति होना संभव है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया केस रेस्पो0 के पक्ष मे साबित माना है एवं अपूर्णनीय क्षति भी रेस्पो0 को होना माना गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिम्मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा न0 883 रकबा 0.8000 एवं 884 रकबा 0.4600 है0 वाके ग्राम थडी को अपीलांट द्वारा करीब 30 वर्ष पूर्व छीतर साई पुत्र माधोसाई से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है। इसी प्रकार रेस्पो0 के अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो0 के पूर्वज स्व0लक्ष्मण की खातेदारी की आराजीयात रही है जिसे सेटलमेंट कर्मचारियो द्वारा गलत तरीके से अपीलांट के नाम दर्ज कर दिया गया। जिसको दुरुस्त कराने हेतु वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर अपीलांट राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा प्राप्त करने पर उतारू है जबकि उक्त गलत इन्द्राज को दुरुस्त कराने का वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। एक्सप्रेस हाईवे मे अवाप्त भूमि के मुआवजा राशि के भुगतान के संबंध मे उभयपक्ष द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) एवं अति0जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहाँ आपत्ति दर्ज कराने के कारण भूमि अवाप्ति अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) एवं अति0जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश सवाई माधोपुर के यहाँ विविध दीवानी प्रकरण संख्या 22/21 पेश किया गया था जिसमे अपीलांट हरिराम पुत्र प्रभूलाल भी बतौर पक्षकार संख्या 5 था। उक्त वाद को माननीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

न्यायालय जिला न्यायाधीश द्वारा अपने निर्णय दिनांक 4.1.25 के द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी(समक्ष प्राधिकारी) को विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज अप्रार्थी संख्या 1 व 6 ता 11 के हिस्से अनुसार मुआवजा राशि अदा करने का आदेश दिये गये है जिसमें अपीलान्त हरिराम को मुआवजा राशि दिये जाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया गया है तथा अपने निर्णय के विवाधक संख्या 1 के द्वारा अपीलान्त हरिराम का कोई क्लेम माना है। विवादित आराजीयात के हक एवं अधिकारों के संबंध में उभयपक्ष के मध्य वाद अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें साक्ष्य सबूतों के उपरान्त उभयपक्ष के हक एवं अधिकारों का निर्धारण हो सकेगा। इस प्रकार अपीलान्त का प्राईमाफैसी केस साबित नहीं होता है तथा अपीलान्त को किसी प्रकार की कोई अपूर्णनीय क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। अतः अपीलान्त की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली के प्रकरण संख्या 1028/18 में पारित निर्णय दिनांक 26.11.18 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.9.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्व अपील प्रमाणिकारी
सवाई माधोपुर